

Before S. S. Sandhwalia, CJ. and M. M. Punchhi, J.

रामफल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1977 की सिविल रिट याचिका संख्या 1598

28 मई, 1980।

पंजाब पुलिस नियम 1934-नियम 16.38 (1) और (2)-एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत में-ऐसी शिकायत तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई-नियम 16.38 (1) का देर से अनुपालन -तत्काल' शब्द का 'महत्व-कहा गया-शिकायत'-जिसका अर्थ है-पुलिस अधीक्षक-शिकायत को जिला मजिस्ट्रेट-पुलिस अधीक्षक को भेजने से पहले कोई जांच करनी है या नहीं-ऐसा सुझाव-क्या जिला मजिस्ट्रेट के विवेक पर अतिक्रमण होता है-विभागीय जांच का आदेश दिया गया है-क्या अपचारी किया गया है।

यह माना गया कि पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 16.38 (1) का अनुपालन अनिवार्य है और यह मुख्य रूप से जनहित के लिए है और इस जनहित में अपचारी अधिकारी और शिकायतकर्ता के साथ-साथ पुलिस बल और आम जनता के हित भी शामिल होंगे। उप-नियम (1) का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना के प्रेषण को पूरी तरह से या उस समय के लिए रोक दिया जाता है जिसे 'उचित' नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें सूचना के प्रेषण में देरी अपरिहार्य हो सकती है। वास्तव में पुलिस अधीक्षक के हाथों में आने वाली शिकायत और दूसरी ओर उसके हाथों से इसकी रिहाई में देरी के कारण देरी हो सकती है। पूर्ववर्ती विलंब नियम के दायरे में नहीं है। यह नियम केवल उस क्षण से लागू होता है जब पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत का अध्ययन किया जाता है और उसे 'क्षणिक जांच' की दिशा में अपनी निष्पक्षता को गति देने का आदेश दिया जाता है। उद्देश्य के लिए आवश्यक समय अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगा, लेकिन पहले से बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं; स्वाभाविक रूप से, मानव निमित्त या दस्तावेजी कार्यवाही, जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के भीतर या उसके बाहर शिकायत को जल्दी से रखने से रोकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक से अपने स्वयं के प्रशासनिक कौशल का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन एक बार शिकायत उसके हाथ में हो जाने के बाद, समय घड़ी चालू हो जाती है। यदि वह शिकायत को आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए रोकता है, तो उसे या तो 'क्षणिक जांच' में देरी करके और/या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी तुरंत भेजकर सार्वजनिक हित का अतिक्रमण करने का जोखिम उठाना पड़ता है। बिना।

कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से संतोष जनक को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि इसमें कोई देरी नहीं चाहिए है और यदि ऐसा था, तो यह इतना अनुचित नहीं था जितना कि नियम के उद्देश्य के साथ असंगत होगा। इसे यह भी प्रतिबिंबित करना होगा कि नियम 16.38 (1) के विलंबित अनुपालन के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ था या नहीं हुआ था और जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता है कि यह न्यायाधीश की विफलता का कारण है, तब तक कार्यवाही दूषित नहीं होगी। (पैरा 10 और 12)।

माना गया कि नियम 16.38 के उप-नियम (1) में 'शिकायत' शब्द को औपचारिक शिकायत तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और इसे इस नियम के तहत निर्दिष्ट किसी विशेष प्रकार के कदाचार के किसी भी आरोप को शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। जब तक पुलिस नियमों में 'शिकायत' शब्द को परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक यह इतना बड़ा महत्व रखता है कि अपचारी पुलिस अधिकारी पर या तो विभाग के

भीतर से या किसी बाहरी एजेंसी से आरोप लगाने की कोशिश कि जा सकती है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की केवल 'क्षणिक जांच' करने की शक्ति होती है कि क्या यह पूरी तरह से उप-नियम (1) के अंतर्गत आती है और इसके नकली होने या एक मजाकिया या देभावनापूर्ण धोखाधड़ी होने की संभावना को दूर करने की शक्ति होती है। उसके पास जांच शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है, हालांकि, शिकायत की सच्चाई का पता लगाने या गुण-दोष पर खुद को संतुष्ट करने के लिए सक्षम रूप से कहा जाता है। उक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को अग्रपिंत की जाने वाली शिकायत को रोक नहीं सकता है और यदि उसे शिकायत की सत्यता पर सवाल उठाते हुए प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति दी जाती है या कोई 'तथ्यात्मक जांच' की जाती है, तो उप-नियम के बाद के हिस्से का स्पष्ट उल्लंघन होगा क्योंकि अततः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित जांच का केवल वही उद्देश्य है। नियम में उपयोग किए गए शब्द 'इंगित' का अर्थ है नुक़ीलापन, जो स्थापना से काफी अलग है। उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समय पुलिस अधीक्षक के साथ रसीद को जोड़ने के लिए एकमात्र समय है शिकायत और जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी का प्रेषण और उस समय, अंतराल क्या होगा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। (पैरा 11)।

यह माना गया कि यह स्पष्ट है कि भारतीय पुलिस अधिनियम व पंजाब पुलिस नियमों के तहत देखे गए जिला अधिकारियों में जिला मजिस्ट्रेट सबसे श्रेष्ठ हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (रैंक में श्रेष्ठ अधिकारी) को दिए गए सुझावों को 'बोलना' या 'साथक या अन्यथा' सुझाव के बराबर नहीं माना जा सकता है। नियम 16.38 (2) व्यापक लोक हित में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यों की निष्पक्षता का आदेश देता है। यह एक और बात है कि क्या उस वस्तुनिष्ठता की पूरी तरह से अभाव बताया जा सकता है या दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया गया। चूंकि नियम 16.38 (2) (2) है। न्यायिक अभियोजन को सामान्य प्रक्रिया और विभागीय कार्रवाई को एक अपवाद के रूप में भी निर्धारित करता है, यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश देने का कारण होता है, यदि सामान्य प्रक्रिया से भटकना है। जैसे की पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को किसी विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने का केवल सुझाव दक्षित नहीं होगा। इसके कारण एक अपचारी अधिकारी के खिलाफ की गई विभागीय जांच ख़ेराब नहीं होगी। (पैरा 20)।

नंद सिंह बनाम। पुलिस अधीक्षक और एक अन्य, 1964 करंट लॉ जर्नल 146,

गोबिंद सिंह बनाम। पुलिस के डी. आई. जी. और एक अन्य, 1964 करंट लॉ जर्नल 150,

वलाईती राम, सॉफ्टा बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य, 1965 करंट लॉ जर्नल 1,

अवतार सिंह उप्पल बनाम पुलिस महानिरीक्षक और अन्य 1966 वर्तमान कानून जर्नल 318,

भजन सिंह बनाम। बहल सिंह, 1967 एस. एल. आर. 601।

ओवररोल्ड।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए सरेशियोरसाई, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त याचिका, निर्देश या आदेश जारी किया जाए।—

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना;

(ii) एन्स में आदेश। रिट याचिका के साथ संलग्न पी-1, पी-7, पी-6 और पी-9 को रद्द किया जाए;

Ram Phal v. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, J.)

(iii) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा और वह वेतन, वरिष्ठता आदि अवशिष्ट की प्रकृति में सभी परिणामी राहतों का हकदार है।;

(iv) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उपयुक्त समझे;

(v) इस याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से जे. एल. गुप्ता, अधिवक्ता

नौबत सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से।

न्याय

मदन मोहन पुंछी, जे.

(1) पंजाब पुलिस नियमों (संक्षेप में "नियम") के नियम 16.38 (1) का देर से अनुपालन एक अपचारी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दूषित करेगा या नहीं, यह एक सवाल है।

प्राथमिक महत्व का, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में उत्पन्न होता है। जैसा कि स्पष्ट है, "तत्काल" शब्द उप-नियम (1) में प्रयुक्त उद्घाटन का प्रमुख शब्द है। यह शब्द, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसने उक्त उप-नियम की व्याख्या के प्रति इसके सही अर्थ, महत्व और आयाम की खोज करने के लिए हमारा गंभीर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन उक्त प्रश्न के अलावा, गौण महत्व के अन्य प्रश्न भी रहे हैं।

¹ (2) सभी विवरणों को छोड़कर, याचिकाकर्ता रामफल का मामला यह था कि 31 मार्च, 1971 को हरियाणा राज्य में सहायक उप-निरीक्षक पुलिस का पद प्राप्त करने से पहले उनका विभिन्न क्षमताओं में एक कर्मचारी के रूप में एक विविध कैरियर था। [वर्ष 1975 में जिला कुरुक्षेत्र के पुलिस स्टेशन, रादौर में तैनात श्री लक्ष्मण सिंह ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने रुपये की अवैध रिश्वत स्वीकार की थी। 550। चौथे प्रतिवादी, कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को 8 सितंबर, 1975 को शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने शिकायत को जिला मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र को भेज दिया-व्यापक ज्ञापन। सं. 1965-पी, दिनांक 24 सितंबर, 1975, जिसकी प्रति 16 दिनों के अंतराल के बाद याचिका के लिए संलग्न पी-1 है। ऐसा पाठ्यक्रम नियम 16.38 (1) के तहत अनिवार्य था जिसे इस समय निरस्त किया जाना उचित है:—

“ 16.38 (1) पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत की तत्काल जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जनता के साथ अपने आधिकारिक संबंधों के संबंध में आपराधिक अपराध करने का संकेत देती है। जिला मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि क्या शिकायत की जांच एक पुलिस * अधिकारी द्वारा की जाएगी, या प्रथम श्रेणी की शक्तियों वाले एक चयनित मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी।

(3) 16 अक्टूबर, 1975 के आदेश के अनुसार, संलग्नक पी-2, जिला मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र ने चौथे प्रतिवादी द्वारा प्रतिनियुक्त एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का आदेश दिया। अपनी वापसी में, चौथे प्रतिवादी ने शिकायत की प्राप्ति की तारीख से लेकर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने तक के 16 दिनों के अंतराल को समझाया है, जिसे पुलिस मुख्यालय के उपाधीक्षक को चिह्नित करके शिकायत पर तथ्यात्मक जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट पर उपरोक्त नियम का अनुपालन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया था, -प्रेषण पत्र, संलग्नक पी-आई के माध्यम से।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र द्वारा अधिकृत जांच की अगली कड़ी के रूप में, कैथल के पुलिस उपाधीक्षक श्री वेद प्रकाश को प्रारंभिक जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष को 6 जनवरी, 1976 को जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के नियम 16.38 (2) के तहत आवश्यक अनुमति के लिए भेजा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का सुझाव दिया गया था। 15 जनवरी, 1976 को जिला मजिस्ट्रेट, संलग्नक पी-4 ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा अन्य प्रासंगिक कागजातों को देखने के बाद द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर अदालत में मुकदमा चलाना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना आवश्यक था, और तदनुसार, उपरोक्त नियम के उप-नियम (2) के तहत अपने विचलित करने वाले विकल्प का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। नतीजतन, एक नियमित जांच की गई और याचिकाकर्ता को रिश्त के रूप में 550 रुपये लेने के आरोप में दोषी पाया गया। अपेक्षित कारण दर्शाओ नोटिस, संलग्नक पी-5, था। 26 जून, 1976 को याचिकाकर्ता को दिया गया, जिस पर उन्होंने 31 अगस्त, 1976 को संलग्नक पी-6 में जवाब प्रस्तुत किया। उनके जवाब और अन्य सामग्री पर विचार करने पर, पुलिस अधीक्षक, करनाल द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 1976 (अनुलग्नक पी-7) को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि 9 जनवरी, 1977 को पुलिस उप-महानिरीक्षक, अंबाला रेंज द्वारा अपील में की गई थी (अनुलग्नक पी-8), और 25 अप्रैल, 1977 (अनुलग्नक पी-9) के अपने आदेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिन संशोधन में हस्तक्षेप करने के लायक नहीं पाया गया था। इस तरह यह मामला याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी में समाप्त होने वाली पूरी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए हमारे सामने लाया गया था।

(5) अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि नियम 16.38 के उप-नियम (1) और (2) अनिवार्य हैं। जगनाथ बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर, (1) में, जे. ग्रोवर ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 16.38 (1) और (2) के प्रावधान अनिवार्य थे और इसके प्रावधानों का पालन किए बिना की गई विभागीय जांच अवैध थी। इस दृष्टिकोण को चानन शाह बख्शी बनाम दिल्ली प्रशासन (2) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा अनुमोदन मिला। उपरोक्त दो निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय (3) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित थे। लेकिन जब दिल्ली

(1) ए. आई. आर. 1962 पी. बी. 38.

(2) 1961 का एल. पी. ए. 68-डी 23 जनवरी, 1963 को तय किया गया।

(3) ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 751.

प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चानन शाह के खिलाफ मामला उठाया, उनके अधिपतियों ने उस मामले में यह तय करना आवश्यक नहीं समझा कि नियम 16.38 के प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका। इस धारणा पर कि नियम निर्देशिका थी, उन्होंने पाया कि उस मामले में, इसके प्रावधानों के पर्याप्त अनुपालन की भी कमी थी। दिल्ली प्रशासन बनाम चनान शाह (3-ए) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त शर्तों पर चनान शाह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय की पुष्टि की गई थी। इस बीच, इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने फिर से नंदन सरूप बनाम जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला और अन्य (4) में दोनों उपनियमों के अनुपालन को अनिवार्य बताया। एक अन्य मामले में, भारत संघ बनाम राम किशन (5) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ (संदर्भ में) यह भी निर्धारित किया कि उक्त नियम के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य थे। लेकिन जब मामले को अपील में सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, तो इस बार उनके लॉर्डशिप्स ने भारत संघ बनाम राम किशन (6) में इस न्यायालय के नियम 16.38 को प्रकृति में अनिवार्य होने के दृष्टिकोण की पुष्टि की। नियम 16.38 (1) और (2) के हितकारी प्रावधानों का अनुपालन एक अपचारी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आवश्यक है। उस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में लाए गए उपरोक्त मामले उप-नियम (1) या उप-नियम (2) या दोनों के अनिवार्य संशोधनों के गैर-अनुपालन के मामले थे। तत्काल मामले में, इस बात का कोई संदेह नहीं है कि नियम 16.38 के दो प्रावधानों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो जोरदार तर्क दिया गया है वह यह है कि नियम 16.38 (1) का विलंबित अनुपालन था और नियम 16.38 (2) का वैध अनुपालन नहीं था।

(6) अब वैधानिक रूप से आवश्यक अनुपालन के लिए, हमें नियम 16.38 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त "तत्काल" शब्द के महत्व की जांच करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया कि "तत्काल" शब्द को इसका सामान्य शब्दकोश दिया जाना चाहिए जिसका अर्थ "जितना संभव हो उतना तत्काल" होना चाहिए। दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त शब्द "तुरंत" शब्द के समान है और इसका अर्थ उस घटना के होने के बाद "उचित समय के भीतर" होना चाहिए जहां से ("तत्काल" शब्द संचालित होता है) उन्होंने यह भी कहा कि "तत्काल" शब्द का संदर्भ एक साथ के पर्यायवाची से नहीं हो सकता।

(3 ए) 1959 (3) एस. सी. आर. 653:

(4) 1966 पीएलआर 747।

(5) 1962 का आर. एस. ए. 256-डी 4 मार्च, 1964 को तय किया गया।

(6) 1972 एस. एल. आर. 11

Bam Phal n. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, J.)

और आवश्यक रूप से पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत की प्राप्ति और जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली इसकी सूचना के बीच एक समय अंतराल का बोझ वहन करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो।

(7) वेंकटरमैया के लॉ लेक्सिकन 1971 संस्करण में "तत्काल" शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है:—

“तत्काल” शब्द का अर्थ है इसे करने के लिए उचित समय देना। परीक्षण यह है कि क्या परिस्थितियों में, ऐसी अनुचित देरी हुई थी जो तत्काल के अर्थ के साथ असंगत होगी।”

आयर के कानून की शर्तों और वाक्यांशों 1973 के संस्करण में, शब्द "तुरंत" का अर्थ समझाया गया है:—

‘तुरंत के समान: जब कानूनों में 'तत्काल' का उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है 'उचित समय के भीतर'।’

कानूनों की व्याख्या पर मैक्सवॉल के 12 वें संस्करण में इस प्रकार कहा गया है:—

“हरमन एल. जे. ने कहा है कि कभी-कभी किसी अधिनियम में किसी कार्य को 'तुरंत' या 'तत्काल' न हो करने की आवश्यकता होती है, यह एक सटीक समय नहीं है और, यह प्रदान करते हुए कि कोई नुकसान नहीं किया जाता है, 'तुरंत' का अर्थ है उसके बाद कोई भी उचित समय इसके बाद कुछ दिनों के भीतर कार्रवाई शामिल हो सकती है: इसमें वर्षों तक कार्रवाई शामिल नहीं हो सकती है।” (जोर दिया गया)।

(8) क्वीन-एम्प्रेस बनाम जम्मू और अन्य (7) में, यह निर्धारित किया गया था कि "तत्काल" शब्द को "उचित समय के भीतर" समतुल्य माना जाना चाहिए और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(9) चानन शाह (बख्शी) के मामले (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने नियमों के नियम निर्माताओं के इरादे को स्पष्ट करते हुए, ग्रोवर, जे. के निर्णय की शुद्धता की जांच करते हुए, जगन नाथ बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर और अन्य (8) में, निम्नानुसार निर्धारित किया:—

“इस निर्णय से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि पूरे नियम 16.38 के प्रावधान हैं

(7) आई. एल. आर. खण्ड। बारहवीं 1889 मद्रास श्रृंखला।

(8) ए. आई. आर. 1962 पी. बी. 38...!

मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए, जबकि मेरी राय में यदि दोनों उप-नियमों के प्रावधानों का अध्ययन किया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि उनका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को अभियोजन या विभागीय जांच से बचाना नहीं है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कोई पुलिस अधिकारी जनता के साथ अपने संबंधों में किसी भी अपराध का दोषी है तो मामले को दबाया नहीं जाएगा। यह नियम के पहले भाग का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है जो जनता के साथ अपने आधिकारिक संबंधों के संबंध में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध करने का आरोप लगाने वाली किसी भी शिकायत के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल जानकारी भेजने का प्रावधान करता है। यह अगले भाग का उद्देश्य भी प्रतीत होता है जो जिला मजिस्ट्रेट से यह तय करने के लिए कहता है कि क्या (पुलिस को स्वयं इस तरह के आरोप की जांच करने की अनुमति दी जा सकती है, या क्या पुलिस से स्वतंत्र रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी चाहिए।”

(10) नियम 16.38 (1) के अनिवार्य अनुपालन पर जोर मुख्य रूप से जनहित के लिए है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि [लोक हित में अपचारी अधिकारी और शिकायतकर्ता; और सामान्य रूप से पुलिस बल और आम जनता का हित भी शामिल होगा। उप-नियम (1) का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना के प्रेषण को पूरी तरह से या उस समय के लिए रोक दिया जाता है जिसे 'उचित' नहीं कहा जा सकता है। समान रूप से जो जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत होनी चाहिए, वह पुलिस अधीक्षक का कार्य केवल रसीद-सह-प्रेषण लिपिक तक सिमित नहीं कर सकती है। पुलिस अधीक्षक को उप-नियम (1) के तहत एक निश्चित कार्य करना होता है, और वह कार्य क्या है जिसे हम स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं।

(11) चनान शाह (बरखशी) के मामले (उपर्युक्त) में यह भी निर्धारित किया गया था कि उपनियम (1) में 'शिकायत' शब्द को औपचारिक शिकायत तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और इस नियम के तहत निर्दिष्ट किसी विशेष प्रकार के कदाचार के किसी भी आरोप को शामिल करने के लिए भी निर्धारित किया जाना चाहिए। दौलत राम बनाम भारत संघ (9) मामले में भी दिल्ली उच्च न्यायालय का यही दृष्टिकोण था। उक्त न्यायालय ने 'शिकायत' शब्द को इसके सामान्य अर्थ में समझने के लिए विस्तृत किया, जिसका अर्थ है संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपराध या कदाचार के किसी भी आरोप, आरोप या जानकारी जो लिखित या मौखिक हो सकती है, या लिखित रूप में हो सकती है।

(#1971 (2) एस. एल. आर. 502.—

Ram Phal v. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, J.)

जनता के किसी सदस्य द्वारा याचिका, या विभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान देने पर, या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा एक गोपनीय रिपोर्ट, या किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, चाहे वह आधिकारिक हो या गैर-आधिकारिक। जब तक कि शिकायत शब्द को पुलिस नियमों में परिभाषित नहीं किया जाता तब तक शिकायत शब्द का बहुत बड़ा महत्व है।

एक बड़ा महत्व, कि अपचारी पुलिस अधिकारी या तो विभाग के भीतर से या किसी बाहरी एजेंसी से एक आरोप लगाने वाली उंगली को आकर्षित कर सकता है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक के पास केवल शक्ति होती है, और यदि हम इस अभिव्यक्ति को शिकायत की 'क्षणिक जांच' के लिए जोड़ सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह पूरी तरह से उप-नियम (1) के भीतर आता है, तो इसके नकली होने या एक मजाकिया या दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी होने की संभावना को दूर करता है। हालांकि, उसके पास शिकायत की सच्चाई का पता लगाने या गुण-दोष के आधार पर खुद को संतुष्ट करने के लिए अल्पकालिक जांच शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है। हरियाणा के वरिष्ठ उप-अधिवक्ता द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया कि पुलिस अधीक्षक के पास इस तरह की प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है या नहीं, इसे अलग रखते हुए वह निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली शिकायत को रोक नहीं सकते हैं। और; यदि पुलिस अधीक्षक को जांच शुरू करने की अनुमति दी जानी है, तो शिकायत की सत्यता या किसी भी 'तथ्यात्मक जांच' पर सवाल उठाते हुए इसे प्रारंभिक कहें, उप-नियम के बाद के हिस्से का स्पष्ट उल्लंघन होगा, क्योंकि अंततः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित जांच का केवल वही उद्देश्य है। नियम जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपनी पसंद की दो एजेंसियों में से किसी एक द्वारा से जांच शुरू करने का आदेश देता है। * वह पुलिस को सामान्य प्रकृति की शिकायतों की जांच करने की अनुमति दे सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवा सकता है। इस आदेश की अनुपस्थिति में, उपनियम (1) के तहत किसी भी जांच की अनुमति नहीं है। जब पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत आयोग से संबंधित होती है; जनता के साथ उसके आधिकारिक संबंधों के संबंध में एक अपराध की, तो 'पलायन जांच' संकेत का पता लगाने के लिए शिकायत पर केवल एक शांत नज़र डालती है, अगर शिकायत किया गया कार्य एक अपराध था, और वह भी जनता के साथ अपचारी अधिकारी के संबंधों के संबंध में। नियम में उपयोग किए गए शब्द 'इंगित' का अर्थ है नुकीलापन, जो स्थापना से काफी अलग है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय केवल पुलिस अधीक्षक के साथ शिकायत की रसीद को जोड़ने और जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी भेजने का समय है, और वह समय अंतराल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(12) हम अभी भी बता सकते हैं की ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें सुचना भेजने में बहुत ज्यादा देरी हो सकती है।

इसकी घटना के दो क्षेत्रों की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में पुलिस अधीक्षक के हाथों में आने वाली शिकायत के पूर्ववर्ती चरण में देरी और दूसरी ओर उसके हाथों से इसकी रिहाई में देरी। पूर्ववर्ती विलंब नियम के दायरे में नहीं है। यह नियम केवल उस क्षण से लागू होता है जब पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत का अध्ययन किया जाता है और उसे 'क्षणिक जांच' की दिशा में अपनी निष्पक्षता को गति देने का आदेश दिया जाता है। उद्देश्य के लिए अपेक्षित समय अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगा, लेकिन पहले से ही बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं; अंतर्निहित, मानव निर्मित या दस्तावेजी कार्यवाही, जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के भीतर या उसके बाहर शिकायत को जल्दी से रखने से रोकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है (अपने स्वयं के प्रशासनिक कौशल का उपयोग करें और हम उनके घर को व्यवस्थित रखने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकते हैं)। लेकिन एक बार जब शिकायत उसके हाथ में हो जाती है, तो समय घड़ी चालू हो जाती है। यदि वह शिकायत को आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए रोकता है, तो उसे या तो 'क्षणिक जांच' में देरी करके और/या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी तुरंत भेजकर सार्वजनिक हितों का अतिक्रमण करने का जोखिम उठाना पड़ता है। उसकी कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से संतोष को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि इसमें कोई देरी नहीं हुई, और यदि कोई थी, तो यह इतना अनुचित नहीं था जितना कि नियम के उद्देश्य के साथ असंगत होगा। इसे यह भी प्रतिबिंबित करना होगा कि मैक्सवेल में पहले हरमन एल. जे. के उद्धरण के आलोक में प्रेषण में देरी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ था या नहीं हुआ था।

(13) हमने इस संभावना पर भी विचार किया है कि पुलिस अधीक्षक, या उनके कार्यालय में एजेंसी, अपचारी अधिकारी को बचाने के लिए और नियम 16.38 के अनुपालन के जानबूझकर उल्लंघन की अनुमति दे सकते हैं ताकि शिकायत को रोक दिया जाए जिस से जनता को परेशानी हो। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस शरारत पर विचार किया गया है, उसे करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और किसी भी मामले में जब यह बताया जाएगा तो न तो कानून अपने कानूनी पाठ्यक्रम से पीछे हटेगा और न ही न्यायालय, किसी उचित मामले में, मामले में उचित राहत देने से पीछे हटेगा, या इसे मौन रूप से देखेगा, और नियम को आत्म-पराजय होने देगा। व्यक्त भय के बावजूद, हमें नियम के गुण पर ध्यान देना चाहिए: यह है कि यह मौजूद है और उपलब्ध है।

(14) अब मामले पर आते हुए, चौथे प्रतिवादी का कहना है कि उसने 8 सितंबर, 1975 को प्राप्त लिखित शिकायत की जांच करने में समय बिताया और शिकायत की जानकारी 24 सितंबर, 1975 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई। उस स्तर पर एक तथ्यात्मक जांच का संचालन स्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लंघन था और

नियम 16.38 (1) की भावना से परे वह तथ्यात्मक जांच 'क्षणिक जांच' के परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करती प्रतीत होती है जो केवल नियम द्वारा आदेशित है जैसा कि हम सार्थक रूप से समझते हैं। निस्संदेह, जिले के पुलिस प्रशासन के प्रमुख होने के नाते क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका होती है और वह अकेले ही गैर-पक्षपातपूर्ण एजेंसी का चयन करने वाले एकमात्र न्यायाधीश होते हैं, जिनसे वह जांच कराएंगे जब एक पुलिस वाले को अपराधी के रूप में आरोपित किया जाता है। उसे अपनी पसंद छोड़ने या देरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्या पुलिस अधीक्षक द्वारा नियोजित ऐसा समय (नियम के उद्देश्य) के साथ अनुचित और असंगत था, या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमें अपने अधिकार क्षेत्र का

Ram Phal v. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, J.)

प्रयोग करने के लिए कोई नुकसान पहुँचाया या किया था, इस पर हम निर्णय में बाद के चरण में एक अन्य संदर्भ के साथ विचार करेंगे।

(15) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य दो तर्कों पर ध्यान देना उचित होगा। वे नियम 16.38 (2) के दायरे में उत्पन्न होते हैं। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

“जब इस तरह की शिकायत की जांच एक प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करती है, तो एक न्यायिक अभियोजन आम तौर पर निम्नलिखित का पालन करेगा: मामला विभागीय रूप से तभी निपटा जाएगा जब जिला मजिस्ट्रेट कारणों को दर्ज करने का आदेश देता है। जब विभागीय रूप से आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाता है तो नियम 16.24 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस नियम में निर्दिष्ट प्रकृति के आरोप में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी को आम तौर पर बखर्स्त कर दिया जाएगा।”

यह तर्क दिया गया कि प्रारंभिक जांच के बाद, 1 जनवरी, 1976 को पुलिस अधीक्षक ने-संलग्नक पी. 3 के माध्यम से, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामले की स्थापना से अवगत कराते हुए आवश्यक फाइल और कागजात जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिए। उसमें आगे यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए नियम 16.38 (2) के तहत आवश्यक अनुमति देने के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा था। यह तर्क दिया गया कि पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं था, और ऐसा करके, उन्होंने न केवल जिला मजिस्ट्रेट के विवेक का अतिक्रमण किया है, बल्कि उनके दिमाग के काम को भी प्रभावित किया है। इस विचार का समर्थन करने के लिए, इस न्यायालय के चार एकल पीठ के फैसलों पर निर्भरता मांगी गई थी

(i) नंद सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य (10) (ii) गोबिंद सिंह बनाम पुलिस का डी. आई. जी. और अन्य (11) जे. (iii) वलाईती राम सोफिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य (12), और अवतार सिंह उप्पल बनाम पुलिस महानिरीक्षक, चंडीगढ़ और अन्य। (13).

(16) नंद सिंह के मामले (ऊपर) में, न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में, निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:—

“जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में तथ्यों पर, जैसा की जाँच में संलग्न है, स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाने और विवेक का प्रयोग करने के अलावा कि सामान्य पाठ्यक्रम का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता पर विभागीय रूप से मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए, पुलिस अधीक्षक ने अपने तथाकथित "स्व-निहित ज्ञापन" में निश्चित रूप से सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले विभागीय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए और विभागीय जांच पूरी होने के बाद, उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई की जा

सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट ने केवल अपने ज्ञापन पर "अनुमत" शब्द लिखा। उन्होंने न्यायालय में न्यायिक सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए विभागीय जांच कराने का कोई कारण नहीं बताया और नियमों के तहत वह इन कारणों को बताने के लिए बाध्य हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया यह रुख कि कोई अलग कारण देने की आवश्यकता नहीं है, असमर्थनीय है "(हमारे द्वारा जोर दिया गया)।

(17) गोबिंद सिंह के मामले (ऊपर) में, पी. सी. पंडित जे. ने इस प्रकार टिप्पणी की:—

“पुलिस अधीक्षक ने तब जिला मजिस्ट्रेट को लिखा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जनता के साथ अपने आधिकारिक संबंधों के संबंध में उसके द्वारा एक आपराधिक अपराध किया गया था और अब तक की अत्यधिक देरी से अपराध को स्थापित करना और प्रमाणित करना मुश्किल हो जाएगा।

- (10) 1964. वर्तमान विधि पत्रिका (पी. बी.)146.
- (11) 1964 वर्तमान विधि पत्रिका (पी. बी.)150.
- (12) 1965 वर्तमान विधि पत्रिका (पी. बी.)1.
- (13) 1966 वर्तमान विधि पत्रिका (पी. बी.)318.

Ram Phal v. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, if.)

कानून की अदालत में चूककर्ता के खिलाफ। इसलिए, उनके द्वारा याचिकाकर्ता के साथ विभागीय रूप से कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया था और उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए नियम 16.38 के तहत आवश्यक जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति मांगी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने तब बिना कोई कारण दर्ज किए पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के अनुसार आवश्यक अनुमति दे दी। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि नियम 16.38 के उप-नियम (1) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए और जिला मजिस्ट्रेट का आदेश बिना कारण बताए आवश्यक मंजूरी के इस नियम के उप-नियम (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।” (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

(18) वलाईती राम सोफटा के मामले (ऊपर) में, जे. शमशेर बहादुर ने नंद सिंह के मामले और गोबिंद सिंह के मामले में कथन का पालन करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“यह जोड़ा जा सकता है कि नियम 16.38 (2) के तहत जो आवश्यक है वह यह है कि “जब ऐसी शिकायत की जांच एक प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करती है, तो एक न्यायिक अभियोजन सामान्य रूप से अनुसरण करेगा, मामले का विभागीय रूप से केवल तभी निपटान किया जाएगा जब जिला मजिस्ट्रेट कारण दर्ज करने का आदेश देता है।” “तत्काल मामले में, नियम 16.38 का दो आवश्यक पहलुओं में उल्लंघन किया गया है। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने स्वयं विभागीय जांच का सुझाव दिया है, और दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट ने इस कार्रवाई के लिए अपने स्वयं के कारण बताए बिना किसी और द्वारा दिए गए सुझाव को अपनी स्वीकृति से अवगत कराया है।” (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

(19) अवतार सिंह उप्पल के मामले (ऊपर) में, तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नरुलाज ने यह निर्धारित करने के बाद कि नियम 16.38 (2) के तहत मामले पर विचार करते समय नियमों के नियम 16.38 (1) का पालन नहीं किया गया था, निम्नानुसार टिप्पणी की:—

“अंत में, श्री पन्नू ने बुआ दास कौशल बनाम पुलिस महानिरीक्षक (14) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ (ए. एन. भंडारी सी. जे. और दौलैत, जे.) के एक गैर-सूचित फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि

(14) 1957 का एल. पी. ए. 169, दिनांक 19 अगस्त, 1958।

जिला मजिस्ट्रेट को एक सिफारिश के साथ रिपोर्ट दी जाती है कि अपीलार्थियों के मामले को विभागीय रूप से निपटाया जाना चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के तहत केवल अपने नाम पर हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त की, यह नियम 16.38 (2) के तहत एक वैध आदेश के बराबर है क्योंकि यह विभागीय कार्य के लेन-देन का सामान्य तरीका है।

यद्यपि एकल पीठ में बैठे विभिन्न विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस न्यायालय के सभी निर्णय उक्त पूर्व के दृष्टिकोण से बहुत सुसंगत नहीं हैं, लेकिन इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही को न केवल विभागीय कार्यवाही की अनुमति देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए सुझाव के आधार पर बल्कि अन्यथा भी दरकिनार किया जा रहा है।”

(20) यह पहले तीन मामलों में हमारे द्वारा दिए गए जोर से स्पष्ट है, निर्णय काफी हद तक इस आधार पर निहित था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक अभियोजन की सामान्य स्थिति से विभागीय जांच की ओर ध्यान भटकाने का कोई कारण नहीं दिया गया था। चौथे मामले में, मुख्य रूप से नियम 16.38 (1) का उल्लंघन करने वालों के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक के सुझाव का केवल जिला मजिस्ट्रेट को भी संदर्भ दिया गया था। उपरोक्त सभी चार मामलों में, अंतिम निर्णय केवल इस विचार पर आधारित नहीं था कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए उक्त सुझाव ने आगे की सभी कार्यवाही को घातक बना दिया। लेकिन अगर यह लिया जाए कि उपरोक्त चार मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को एक विशेष मार्ग अपनाने का सुझाव अपने आप में घातक है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस सीमित सीमा तक उसमें व्यक्त कानून का दृष्टिकोण सही नहीं है और हम उसी पर सहमत होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। उस सीमित सीमा तक, यह दृष्टिकोण अति-शासित है। यह स्पष्ट है कि भारतीय पुलिस अधिनियम और पंजाब पुलिस नियमों के तहत देखे जाने वाले जिला अधिकारियों में, जिला मजिस्ट्रेट सबसे श्रेष्ठ है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (रैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी) को दिए गए सुझावों को 'निर्देशित' या 'सार्थक या अन्यथा' सुझाव के बराबर नहीं माना जा सकता है। नियम 16.38 (2) जिला मजिस्ट्रेट के कार्यों के प्रति निष्पक्षता का आदेश देता है, फिर से व्यापक सार्वजनिक हित में। यह एक और बात है कि क्या उस वस्तुनिष्ठता को पूरी तरह से कमी के रूप में इंगित किया जा सकता है या कोई दिमाग का प्रयोग नहीं था।

चूंकि नियम 16.38 (2) न्यायिक अभियोजन को सामान्य पाठ्यक्रम और विभागीय कार्रवाई को एक अपवाद मानता है, इसलिए यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारण देने का आदेश देता है, यदि सामान्य पाठ्यक्रम से विचलित होना है।

(21) याचिकाकर्ता का अगला तर्क यह है कि जिला मजिस्ट्रेट ने न तो मामले पर अपना दिमाग लगाया और न ही विभागीय कार्यवाही शुरू करने के अपवाद को प्राथमिकता देने का कोई कारण बताया। लेकिन अगर संलग्न पी-4 को पढ़ना है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा उनके सामने रखे गए अन्य कागजातों को देखा तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता पर अदालत में मुकदमा चलाना अनुचित पाया। फिर भी, न्याय के आगे के उद्देश्यों के लिए, उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना आवश्यक समझा। चीजों की प्रकृति में यदि न्यायिक अभियोजन को खारिज कर दिया गया था, तो जिला मजिस्ट्रेट के लिए एकमात्र अन्य रास्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसका कारण स्वयं स्पष्ट था। इस प्रकार आदेश नियम 16.38 (2) के तहत आवश्यक कारणों से रहित नहीं है, जिसे सुरक्षित रूप से काफी हद तक अनुपालन के रूप में माना जा सकता है।

(22) अंत में, दोनों पार्टियों के वकीलों द्वारा राज कुमार बनाम पंजाब राज्य (15) मामले में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले पर एक-दूसरे की संबंधित दलीलों को ध्वस्त करने के लिए भरोसा रखा गया था। जहां याचिकाकर्ता के वकील ने अवतार सिंह उप्पल के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के एकल पीठ के फैसले से सहायता मांगी, जिसमें नियमों के नियम 16.38 (1) में "तत्काल" उपस्थित होने वाले न्यायाधीश को पूर्ण प्रभाव दिया गया था, और तीन महीने से अधिक समय तक सूचना के विलंब को जांच के लिए घातक माना गया था, प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा ने तर्क दिया कि (पूर्ण पीठ के उनके अधिपत्य के बावजूद, उन्होंने आपराधिक अभियोजन में आरोप को रद्द करने के बाद, अभियोजन पक्ष के लिए एक नया मार्ग खोलकर नियम 16.38 के द्वारा विचार की गयी जाँच के आधार पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक नई रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य को एक मार्ग की अनुमति दी है। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि रिल्स के नियम 16.38 (1) के उल्लंघन के बावजूद, राज्य को नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने की अनुमति दी गई है, इस बात की अनदेखी करते हुए कि शिकायत की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत चुका है

(15) 1976 (1) एस. एल. आर. 5.

शिकायत की तारीख और पूर्ण पीठ द्वारा आरोप को रद्द करना। पहली बात यह कि राज कुमार के मामले (ऊपर) में उपरोक्त पूर्ण पीठ का निर्णय तत्काल मामले पर लागू नहीं होगा। वह (नियम 16.38 (1) के पूर्ण गैर-अनुपालन का मामला था, लेकिन हाथ में मामला स्पष्ट अनुपालन का मामला है, लेकिन एक विलंबित मामला है। दूसरे स्थान पर, पंजाब राज्य बनाम गुरबक्स सिंह (16) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों ने यह निर्धारित किया है कि यह निर्धारित करना गलत था कि नियम 16.38 का अनुपालन न्यायालय में एक पुलिस अधिकारी के अभियोजन के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी, और नियम का एक सादा अध्ययन दर्शाता है कि इसका आवेदन केवल विभागीय पूछताछ तक ही सीमित है। उनके अधिपतियों ने इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के निर्णय को मंजूरी दी, जिसे होशियार सिंह बनाम पंजाब राज्य (17) के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक पुलिस अधिकारी को

मुकदमे के लिए भेजे जाने से पहले जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी आदेश देना अनिवार्य नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि राज कुमार के मामले (ऊपर) में इस अदालत की पूर्ण पीठ ने होशियार सिंह के मामले (ऊपर) को खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होशियार सिंह के मामले को मंजूरी दे दी है: जाहिर है, पहली नज़र में, पूर्ण पीठ का मामला जिसमें नियम 16.38 (1) का पालन न करने के लिए आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। और यदि ऐसा है, तो हमारे लिए जो बचा है वह स्वतंत्र रूप से अवतार सिंह उप्पल के मामले (ऊपर) में जे. नरूला द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर विचार करना है, जैसा कि भजन सिंह बनाम बहल सिंह (18) में उनके द्वारा किया गया था, पूर्व निर्णय को राज कुमार के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ था।

(23) अवतार सिंह उप्पल के मामले (उपरोक्त) में, याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा उस समय खटखटाया जब उसके खिलाफ विभागीय जांच लंबित थी और उसने शिकायत की थी कि नियम 16.38 (1) का पालन नहीं किया गया क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत जानकारी नहीं दी गई थी। जे. नरूला ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:—

“वैधानिक नियम का प्रभाव हर शब्द पर दिया जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल जानकारी नहीं दिए जाने और वास्तव में तीन महीने से अधिक समय से उसे कोई जानकारी नहीं दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी जांच कार्यवाही दूषित हो जाती है और उपरोक्त अनिवार्य नियम का पालन न करने के कारण अमान्य हो जाती है।”

(16) क्र. 1975 की ए 114 का निर्णय 15 नवंबर, 1979 को लिया गया।

(17) 1965 पी. एल. आर. 438

(18) 1967 एसएलआर 601.

उस मामले में तत्कालीन याचिकाकर्ता को उनके उपनिरीक्षक के मूल पद को वापस करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उनके खिलाफ पूरी लंबित जांच और विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। इसी तरह, जे. नरूला ने भजन सिंह के मामले (ऊपर) में अवतार सिंह उप्पल के मामले (ऊपर) में अपने पहले के विचार की पुष्टि करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:—

“पुलिस नियमों के नियम 16.38 (1) के शुरुआती भाग में 'तत्काल' शब्द के प्रभाव और प्रभाव के बारे में अवतार सिंह के मामले (ऊपर) में मैंने जो विचार लिया, उससे अलग होने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। इतने लंबे समय के बाद उक्त नियम का सहारा लेने की अनुमति देना, मेरी राय में, उक्त नियम की वैधानिक आवश्यकताओं की अनदेखी करने के बराबर होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि अंबाला रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक (अनुलग्नक) का आदेश, जो इस स्तर पर मामले को जिला मजिस्ट्रेट, रोहतक के समक्ष रखते हुए पुलिस नियम 16.38 (1) के प्रावधानों के अनुपालन का निर्देश देता है, जे कानून के प्रावधानों के विपरीत है, और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। रोहतक के पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित सजा के आदेश को रद्द करने वाला अपीलीय प्राधिकरण का आदेश स्पष्ट रूप से सही है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

उस मामले में याचिकाकर्ता को जांच का सामना करना पड़ा था और उसे सहायक उप-

Ram Phal v. State of Haryana and others (M. M. Punchhi, J.)

निरीक्षक के अपने मूल पद पर वापस भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता की अपील पुलिस उप-महानिरीक्षक, अंबाला रेंज के समक्ष लंबित थी। इस बीच, पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कई अन्य पूछताछ की और ऐसी ही एक जांच विचाराधीनता रहने के दौरान याचिकाकर्ता को चेतावनी दी गई। यह उस स्तर पर था जब याचिकाकर्ता इस अदालत में आया था और पुलिस अधीक्षक को विभागीय जांच के संबंध में अपने आदेश और नोटिस वापस लेने का निर्देश देने की मांग की थी। रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, पुलिस उप महानिरीक्षक ने नियम 16.38 (1) का पालन न करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर नियम 16.38 (1) का पालन करने के लिए मामले को पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। यह इस क्रम में है कि पूर्व उद्धृत टिप्पणियाँ जे. नरुला द्वारा की गई थीं, और इस तरह का अनुपालन प्राप्त करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशों को रद्द कर दिया गया था।

(24) अब, यह देखा जाएगा कि उपरोक्त दो मामलों में याचिकाकर्ताओं ने चरणबद्ध तरीके से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जब मामला था

विभागीय अधिकारियों के समक्ष एक या दूसरे स्तर पर लंबित था, और नियम 16.38 (1) का पालन करने के लिए प्रयास किया जा रहा था या उनकी ओर से प्रयास किया गया था, हालांकि देर से। "उक्त उप-नियम में प्रयुक्त "तत्काल" शब्द के संबंध में उपरोक्त दो निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण हमें बहुत अधिक वैध प्रतीत होता है और हमारे द्वारा जल्दी और अभी व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अवतार सिंह उप्पल के मामले (ऊपर) और भजन सिंह के मामले (ऊपर) में न्यायाधीश नरुला द्वारा व्यक्त किए गए विचार 'तत्काल' के संबंध में खारिज हो जाएंगे। और किसी भी मामले में, वे मामले थे जिनमें मामला इस न्यायालय में तुलनात्मक रूप से पहले के चरणों में उठाया गया था या विभागीय अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था, और इस प्रकार उनके अपने तथ्यों पर निर्णय लिया गया था।"

(25) ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों के समक्ष कभी भी नियम 16.38 (2) का त्रुटिपूर्ण अनुपालन नहीं उठाया गया है। इन याचिकाओं के संबंध में कारण-प्रकट नोटिस (अनुलग्नक पी. 6), बर्खास्तगी का आदेश (अनुलग्नक पी. 7), अपीलीय आदेश (अनुलग्नक पी. 8) और पुनरीक्षण आदेश (अनुलग्नक पी. 9) का जवाब पूरी तरह से मौन है। याचिकाकर्ता द्वारा जाँच में भाग लेने और विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील और पुनरीक्षण के अपने उपायों का लाभ उठाने के बाद इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत किया, शायद इस उम्मीद पर कि उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें अब और विशेष रूप से इस याचिका द्वारा से नियम 16.38 (1) के विलंबित अनुपालन के संबंध में इन प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, बिना यह अनुरोध किए कि उनके साथ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है। याचिका इस बारे में काफी मौन है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी भेजने में देरी और तथ्यात्मक जांच करके उस समय की नियुक्ति से उसे क्या बुरा परिणाम हुआ है। केवल यह अनुरोध किया गया है कि देरी नियम 16.38 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और पूरी कार्यवाही को दूषित करती है, लेकिन नियम 16.38 (1) के सुझाए गए विलंबित अनुपालन के कारण किसी भी स्तर पर कोई अन्याय नहीं हुआ। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तत्काल मामले में, पुलिस अधीक्षक को ईमानदारी से विश्वास हो सकता है कि वह मामले को जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी के लिए रखने से पहले एक संक्षिप्त ^{तथ्य} 1 जांच करने का हकदार था। यह समान रूप से हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक ने माना कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के अंत में संदर्भ और निपटान की सुविधा के लिए शिकायत में दिए गए कथनों की छान-बीन करने के लिए जनहित में काम किया था। हमें (उसी समय, यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि यह नहीं लिया समझा जाना चाहिए कि हम

लक्ष्मण दास और एक अन्य बनाम मदन लाल (डी. एस. तेवतिया, जे.)

ने पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या किया गया है, इसके बारे में स्पष्ट मंजूरी दी, लेकिन किसी भी दुर्भावनापूर्ण आरोप की अनुपस्थिति में, यह मानने की संभावना है कि दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से अनुचित नहीं है जो हमारी अस्वीकृति को पूरी तरह से पूरा कर सकता है; इससे भी अधिक, जब नियम न्यायिक मार्गों से स्पष्टता की मांग कर रहा है। इस प्रकार हम इसे ऐसा मामला नहीं पाते हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायाधीशालय की अधिकार क्षेत्र का उपयोग याचिकाकर्ता के पक्ष में, सामने लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को किसी भी महत्वपूर्ण नुकसान या न्यायाधीश की विफलता के बारे में बुद्धिमान बनाए बिना किया जाना चाहिए।

(26) उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, इस याचिका को विफल होना पड़ता है और खर्च के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

एस. एस. संधवालिया, /सी. जे.-में सहमत हूँ।

एन के एस।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

nar singh translator

डी. एस. तेवतिया से पहले, जे.

लक्ष्मण दास और एक अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

मदन लाल, -प्रतिवादी।

1974 का सिविल संशोधन सं. 1491

18 जुलाई, 1980।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III)-खंड 13 (2) (ए) (iii) और 13 (4)-एक विकास योजना के तहत सुधार न्यास द्वारा कब्जा किए गए किरायेदार के साथ खरीदारी करें-योजना के क्षेत्र के भीतर आने वाली दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाए और नई दुकानों का निर्माण किया जाए-मकान मालिक को एक नई दुकान आवंटित की जाए-जिसमें से किरायेदार को बेदखल कर दिया गया था-किरायेदार खंड 13 (4) के तहत कब्जे की बहाली के लिए आवेदन कर रहा है-ऐसा आवेदन-चाहे वह बनाए रखने योग्य हो-खंड 13 (4) के प्रावधान-चाहे वे आकर्षित हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां किसी किरायेदार को विकास योजना के तहत सुधार न्यास द्वारा भवन से बेदखल किया गया है, उसे किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के

निष्पादन में बेदखल नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, सुधार न्यास को उसके कब्जे के समर्पण को उसकी बेदखली नहीं माना जा सकता है।